नईदुनिया
दिल्ली-एनसीआर, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रायपुर, बिलासपुर और भोपाल (नवदुनिया)
मुंबई, लखनऊ, पटना, रांची, जयपुर, चंडीगढ़ और देहरादून से प्रकाशित

सरकार की नजर में भारत में जाति समस्या नहीं

भाषा सिंह

नई दिल्ली। भारत सरकार की मानें तो देश में जाति और जाति उत्पीड़न जैसी कोई समस्या ही नहीं है। पिछली सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ की नस्ली भेदभाव पर हुए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में देश में दलित उत्पीड़न और भेदभाव से ही इनकार कर दिया था। इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाति की समस्या से ही भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इनकार कर दिया था। इसी आधार पर सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के किसी जांच समूह को भारत आने की इजाजत भी नहीं दी। इस सम्मेलन के जो दस्तावेज नईदुनिया को मिले वह सच्चाई से मुंह मोड़ने वाले हैं।

संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में दलित उत्पीड़न से इनकार कर दिया था पिछली सरकार ने

पिछली सरकार का यह रवैया मौजूदा सरकार के सामने एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। नई सरकार ने मीरा कुमार को लोकसभा अध्यक्ष बनाकर दलित कार्ड चलते हुए जाति भेदभाव मिटाने का ऐतिहासिक घोष किया। वहीं कांग्रेस नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच पर यह कह कर पल्ला झाड़ लिया कि जाति और नस्ली भेदभाव अलग है। सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि भारतीय कानून सबको समान अवसर देता है। हम अपनी समस्याएं खुद निपटा सकते हैं। पूरी तरह से विरोधाभासों से भरे इस रुख का विरोध करते हुए सम्मेलन में शिरकत करने गए दलित मानवाधिकार संगठन के पॉल दिवाकर ने बताया कि इस आधार पर तो भारत को अपना दल ही नहीं भेजना चाहिए था। वैसे भी संयुक्त राष्ट्र की नस्ली भेदभाव की परिभाषा में नस्ली तथा अन्य उत्पीड़न आते हैं, जिसमें जातिगत उत्पीड़न को भी शामिल माना जाता है।

सम्मेलन में देश की सिविल सोसायटी की तरफ से जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न पर पर्चा पढ़ने वाले सफाई कर्मचारी आंदोलन के नेता विल्सन बेजवाडा का कहना है कि झूठा दंभ भरकर या समस्या से मुंह चुराकर सरकार ने इस समस्या का हल खोजने का एक और मौका खो दिया। देश में वही सरकार दलितों को रिझाने के लिए दलित महिला स्पीकर चुन रही है। कोई उनसे पूछे कि जब जाति समस्या या उत्पीड़न देश में नहीं है तो दलित महिला का स्पीकर बनना क्यों ऐतिहासिक है?